मेहनतकशों का पैग़ाम — मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- प्रशासन के मालिक कुछ खुद भी कर के दिखायें उपायुक्त का भाषण: बच्चे सिखायें, खुले में शौच न जायें — 3
- डॉ. नामवर सिंह: हिंदी साहित्य का रंगा हुआ सियार — 4
- तुम्हे खाते देख फरिश्तों का भी पेट भर जाएगा इरोम
- यूपी चुनाव - लुटेरों और दंगाइयों के बीच फंसी जनता — 5
- झूठ बोलने में माहिर कृष्णपाल गूजर — 8
- गूजर के प्रबल विरोध के बावजूद विपुल बने मन्त्री

वर्ष 29 | अंक 18 | फरीदाबाद, सोमवार 1-15 अगस्त 2016 | फोन : - 9999595632 | 2 ₹

मोदी सरकार का स्टार्ट-अप/स्टैंड-अप से हैंड्स-अप तक का सफ़र

महंगाई का 'डाटा' यानी टमाटर-आलू-दाल आतंक!

दाल काली करके अडानी ने एक लाख नब्बे हज़ार करोड़ मुनाफ़ा कूटा

संसद को भी अंततः कमरतोड़ महंगाई पर थूक बिलोने का मौका मानसून सत्र में मिल ही गया। मोदी सरकार की ओर से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दलील दी कि महंगाई तो उन्हें विरासत में मिली है। कमाल की लाचारी है यहां जो सरकार स्टार्ट अप इन्डिया और स्टैंड अप इन्डिया के विज्ञापनी नारों से अपना महिमा मंडन कर रही है, उसने इतनी जल्दी लाचारी का हैंडस अप भी कर दिया? दरअसल विरासत में तो मोदी-जेटली को अडाणी और अम्बानी मिले थे। महंगाई के पीछे भी वही और उन जैसे तमाम भाजपा समर्थक जमाखोरों-मुनाफ़ाखोरों की जमात है।

मज़दूर मोर्चा, दिल्ली ब्यूरो

केन्द्र की भाजपा सरकार के बारे में अरविंद केजरीवाल का यह कथन एकदम सही उतर रहा है कि इनकी एक जेब में अडानी है ओर दूसरी में अम्बानी। इस साल के बजट में मोदी-जेटली जोड़ी ने कार्पोरेट लॉबी को 65000 करोड़ की टैक्स माफ़ी दी है। यह वही सरकार है जो किसानों को चन्द हज़ार रुपयों की कर्ज़ अदायगी में देरी के लिये जेलों व आत्महत्याओं का रास्ता दिखाती है। आज अगर आम भारतीय की थाली में दाल की कीमत आग लगा रही है तो इसका

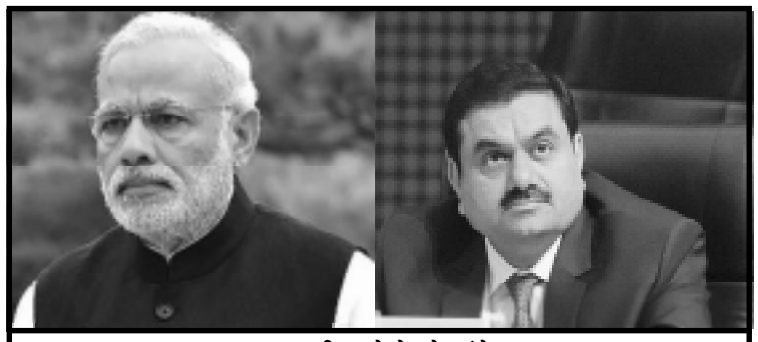

दाल काली करने के दो सांझेदार

श्रेय मोदी और अडानी की व्यक्तिगत दोस्ती एवं साझेदारी को दिया जायेगा।

गुजरात में यह जानकारी आम है कि गत 15-20 वर्षों में अडानी का आर्थिक साम्राज्य दिन दूणी रात चौगुणी गति से इस लिये बढ़ पाया है क्योंकि उसमें नरेन्द्र मोदी का काला धने बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। ऐसे में अडानी की दाल बाज़ार में दिलचस्पी की दाल की कीमतों में वृद्धि से सम्बन्ध समझना मुश्किल नहीं है। आज दिल्ली में दाल की कीमतें 150 रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर चल रही हैं। चन्द माह पहले ये 220 रुपये तक पहुंच गयी थी। ध्यान रहे कि दाल की कीमतों ने 2014 से पूर्व कभी भी 100 रुपये का आंकड़ा पार नहीं किया था।

2014 में आखिर ऐसा हुआ क्या? 2014 में 100 दिन में महंगाई घटाने के वायदे पर सवार होकर मोदी सरकार सत्ता में आई। सरकार बनते ही अडानी ने सिंगापुर की विलमर कम्पनी के साथ मिल दालों की बड़े पैमाने पर भारतीय किसानों से खरीदने और गोदामों में भरने का साझा उपक्रम शुरू किया। उस समय तक इस तरह की खरीद और संग्रह पर एक कानूनी सीम थी, जिसे सरकारी आदेश से खत्म करा दिया गया। यानी अडानी जितना चाहता उतनी दाल खरीद कर अपने गोदामों में भरने को स्वतंत्र हो गया। अन्ततः 3 मुख्य दाल उत्पादक राज्यों के किसानों से तमाम दाल इस कम्पनी द्वारा खरीद ली गयी। खरीद की दर थी 30 रुपये प्रति किलो ग्राम और खरीदी गयी दाल की मात्र थी सौ लाख टन।

एक तरह से देश का पूरा दाल व्यापार अडाणी की मुट्ठी में आ गया और वह 30 रुपये के भाव खरीदी दाल को 220 रुपये तक बेच गया। कुल मुनाफ़ा हुआ एक लाख नब्बे हज़ार करोड़ का। संसद में अरूण जेटली के मुंह से सचाई निकल ही गयी कि चीज़ों के दाम मांग और आपूर्ति के समीकरण से तय होते हैं। बस वे यह बताना भूल गये कि उनके बॉस नरेन्द्र मोदी के दोस्त गौतम अडानी ने यही तो किया था। दाल की मांग तो ज़्यों की त्यों बनी रही लेकिन अडाणी ने आपूर्ति अपने गोदामों में कैद कर ली। दाल और अडानी तो महंगाई के मात्र एक पक्ष हैं। फ़िलहाल सब्ज़ियों को ही लें तो आलू और टमाटर के दाम भी रिकॉर्डतोड़ गति से चढ़ते गये हैं। विशेषकर आलू तो ग़रीब से ग़रीब परिवार के खाने का भी एक अभिन्न हिस्सा होता है। यानी देश में शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी जेब में डाका डाल कर बिचौलियों की तिजोरियां ना भरी जा रही हों। भाजपा मुख्यतः इसी बिचौलिया वर्ग के हितों की देखभाल करने वाली पार्टी है। लिहाज़ा उसे उपभोक्ता या किसान के लुटने की ज़रा भी परवाह नहीं होती। प्याज के उदाहरण से यह खेल अच्छी तरह समझा जा सकता है। आज यदि किसान अपनी प्याज बाज़ार में बेचने जाय तो उसे 2-4 रुपया का भाव भी नहीं मिलता। मध्यप्रदेश में तो सरकार किसानों से 5 रुपये किलो प्याज खरीदकर स्वयं को किसान हितैषी होने का प्रमाणपत्र देने में जुटी है। पर जैसे ही किसान के पास प्याज खत्म हो जायेगी, बिचौलियो का खेल शुरू हो जायेगा। वे अपने गोदामों से थोड़ी-थोड़ी प्याज निकाल कर बाजारों में लायेंगे जिससे धीरे-धीरे कीमतें बढती चली जायें। कुछ ही महीनों में हम पायेंगे कि 4 रुपये वाली प्याज 40 रुपये में भी नहीं मिल रही। उस समय मोदी, जेटली ओर उनकी तमाम सरकारी मशीनरी कानों में तेल डाल कर सोई पड़ी मिलेगी।

यह है महंगाई का 'टाडा' जिसके रहस्य की कुंजी मोदी-जेटली की जेब में है। न यह जेब से बाहर आयेगी और न जनता के ऊपर से इस 'टाडा' का आतंक उतरेगा। तब तक जनता 'हर-हर मोदी' की जगह 'अरहर मोदी' बोल कर गुजारा करने को स्वतंत्र है। लोगों के पास एक और विकल्प है मोदियों,-जेटालियों को 'शट अप' कहने का।

हुड्डा-वाड्रा को जेल तो कैसे अलग मोदी-अडानी का खेल

कयास हैं कि राबर्ट वाड्रा के भूमि सौदों में ढींगरा आयोग की रिपोर्ट वाड्रा और हुड्डा को जेल भेजने का मार्ग प्रशस्त करेगी हालांकि ऐसे आयोगों का जो हश्र होता है वह सभी जानते हैं, इसलिये हुड्डा/वाड्रा का बाल भी बांका न हो पाये तो कोई ताज्जुब नहीं। तो भी क्या इसी आधार पर दाल सौदों को लेकर मोदी-अडाणी पर भी आयोग नहीं बैठेगा? हालांकि इसका नम्बर 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद ही आयेगा जब मोदी हार कर सत्ता के कूड़ेदान में पहुंच चुका होगा।

ख़बर दार

गौ (रक्षकों) का अन्तिम संस्कार

गौ रक्षा के नाम पर गुजरात व अन्य राज्यों में दलितों को पीटने व अपमानित करने का सिलसिला थम नहीं रहा। बसपा की सुप्रीमो मायावती ने भाजपाईयों को ललकारा है कि जिस गौ माता को माता कहते हो उसका अन्तिम संस्कार भी तो किया करो। पृष्ठभूमि यह है कि गुजरात में प्रताड़ित दलितों ने मरी गायों को बजाय पहले की तरह स्वयं ठिकाने लगाने के अब सवर्ण दबगों व सरकारी कार्यालयों के सामने डालना शुरू कर दिया है। लगता है यह दलित उभार अगले वर्ष उत्तर प्रदेश और गुजरात के विधान सभा चुनाव में भाजपा के अन्तिम संस्कार का रास्ता खोल देगा। प्रस्तुत है मायावती से एक काल्पनिक साक्षात्कार।

म.मो-बहन मायावती जी आप गौ रक्षकों से कहां भिड़ गयीं?

मायावती- अरे भई अगर ये गौ रक्षक हैं तो हम भी तो गौ पातक हैं। ये गाय का दूध पीते हैं लेकिन मरने के बाद गाय का अन्तिम संस्कार तो हम ही यानी दलित ही करते आये हैं।

म.मो.-फ़िर ये गौ रक्षक दलितों को ही प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं? उनकी रोज़ी-रोटी में बाधा क्यों पैदा कर रहे हैं?

मायावती-जाहिर है इनका एकसूत्री कार्यक्रम हिन्दू वोट-बैंक बनाना है। हिन्दुओं की न तो इनसे महंगाई दूर होती है और न उन्हें रोज़गार दे सकते हैं। गुजरात में पटेल और हरियाणा में जाट उनके खिलाफ़ आरक्षण की तलवार निकाले खड़े हैं। ऐसे में गाय माता ही इनके पास एकमात्र विकल्प रह जाता है।

म.मो.-लेकिन ये गौ रक्षक तो दलितों के पारम्परिक चमड़ा व हड्डी व्यापार पर चोट करने में लगे हैं?

मायावती-इसके पीछे निर्यात बढावा देने के नाम पर लगाये गये बड़े-बड़े बूचड़खाने हैं जो भाजपा समर्थक सवर्णों द्वारा चलाये जा रहे हैं अगर दलितों को खाल हड्डी के कारोबार से बाहर कर दिया जाये तो इन बूचड़खानों की चांदी हो जायेगी। क्योंकि तब बूढे और बेकर पशुओं को लोग मरने से पहले इन बूचड़खानों को बेच दिया करेंगे।

म.मो.-बहन जी आप गौ रक्षकों की भावनाओं की अवहेलना कैसे कर सकती हैं? आखिर वे गया को माता मानते हैं।

मायावती-ये भाजपाई तो मुझे भी बहन माना करते थे। आज गली-गली मुझे गालियां देते घूम रहे हैं। इसी पार्टी के उपाध्यक्ष ने मुझे वे... तक कह डाला। आप सोच सकते हैं कि गाय के प्रति इनकी भावनायें कहां तक सच्ची हैं।

म.मो.-ये गाय को मां तो कहते ही हैं।

मायावती-यह मैं तब मानूंगी जब ये लोग हर उस उस डेयरी वाले को नाना कह कर बुलाना शुरू करेंगे जो मायों को पालता है।

असंवैधानिक सिफ़ारिशें हैं वेतन आयोग की

सातवे वेतन आयोग ने खुलेआम वेतनवृद्धि की असंवैधानिक सिफ़ारिशें की हैं। जिन्हें मोदी सरकार ने लागू भी कर दिया है। कमाल की बात यह है कि सिफ़ारिशों के असंवैधानिक पहलू पर न तो असंतुष्ट कर्मचारीगण बात कर रहे हैं और न ही विपक्षी राजनीतिक दल।

संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में एक यह भी है कि सरकार विभिन्न वर्गों के बीच आय की असमानता को कम करने की दिशा में काम करेगी। जबकि ठीक इसके विपरीत आयोग ने आय की असमानता को बेहद बढ़ाने का काम किया है।

नये वेतनमान लागू होने से पहले कनिष्ठतम कर्मचारी का वेतन 8000 रुपये मासिक और वरिष्ठतम का 80000 रुपये मासिक होता था। यानी दोनों के बीच 72000 रुपये और 10 गुणे का फ़र्क था। नये वेतनमान के अनुसार अब कनिष्ठतम कर्मचारी को जहां 18000 मासिक मिलने जा रहे हैं वहीं वरिष्ठतम् अफ़सर की पगार 2 लाख 50 हज़ार मासिक होगी। इस तरह दोनों के बीच का अन्तर बढ कर 14 गुणा हो गया है। खालिस रुपयों में यह अन्तर 2 लाख 32 हज़ार रुपये तक जा पहुंचा है।

इस असंवैधानिक विसंगति पर सभी राजनीतिक दल इस लिये खामोश हैं क्योंकि वर्गीय नज़रिये से वे भी वरिष्ठ नौकरशाहों का ही हितपोषण करते हैं। रही बात कनिष्ठ कर्मचारियों की तो उनके सामने दो-चार हज़ार की और वेतनवृद्धि का चारा फ़ेंक दिया गया है।

क्या इस घोर असंवैधानिक वेतन वृद्धि को कार्मिक संगठनों एवं संविधानविदों द्वारा अदालतों में चुनौती दी जायेगी?